

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—323/2011/225 (2011/00074)

1. काली पत्नि भागीरथ पुत्री चौथू जाति बागरिया, निवासी रामपुरा भूरटिया तहसील दूदू मु० मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. लादी पत्नि सूरजकरण पुत्री चौथू जाति बागरिया, नि० रामपुरा भूरटिया, तह० मौजमाबाद हाल निवासी पचाला, तह० फागी, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. बन्ना,
2. देवा,
3. रामचन्द्र,
पुत्रान चौथू निवासी ग्राम रामपुरा भूरटिया, तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर
4. मेवा,
5. रूपा,
पुत्रान स्व० भूरा नाबालिगान संरक्षक जरिये माँ रतनी, निवासी रामपुरा भूरटिया, तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
6. घासी पुत्र चौथू मु० लादू जाति बागरिया, नि० रामपुरा भूरटिया, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
7. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 19.7.2011 अंतर्गत वाद संख्या 92/2011.

उपस्थित:—

1. श्री एन०एस० पारीक, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पोंड संख्या 1 से 6 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पोंड संख्या 7.

निर्णय

दिनांक:— 30.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय दिनांक 19.7.2011 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोंड संख्या 6 ने रेस्पोंड संख्या 1 लगायत 5 के विरुद्ध वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजकाशत अधी के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 25 के आराजी खसरा नंबर 756 रकबा 1.77 है, खसरा नंबर 757 रकबा 0.53 है, खसरा नंबर 891 रकबा 0.71 है कुल किता 3 कुल रकबा 3.01 है भूमियां वाके ग्राम रामपुरा उर्फ भूरटिया, तह मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसका प्रार्थी 1/2, हिस्से का, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 हिस्सा 1/2 के खातेदार काशतकार है एवं काबिज काशत है । विवादित आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त हिस्सेनुसार अविभाजित आराजियात है परन्तु मौके पर पक्षकारान ने आज से काफी वर्षों पूर्व अपने-अपने हिस्से का बाहमी बंटवारा कर लिया है तथा मौके पर मेडबंदी कर ली है । विवादित आराजियात का राजस्व रिकार्ड में तकासमा नहीं होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन मेर, कोर को लेकर विवाद रहने लगा है । प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी को काफी उन्नत व उपजाउ बना लिया है जिससे अप्रार्थीगण की नियत में फितुर आ गया है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 में प्रार्थी को उसके 1/2 हिस्से से बेदखल नहीं करे न ही प्रार्थी के कब्जे काशत में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । विद्वान अधीन्याया ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 19.7.2011 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को इस अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि आगामी आदेशों तक वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नंबर 756, 757 व 891 कुल रकबा 3.01 है वाके रामपुरा उर्फ भूरटिया, तह मौजमाबाद में रिकार्ड खातेदार वादी के नाम दर्ज हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे । अधीन्याया के इस अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड को तलब किया गया । रेस्पोंड बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधीन्याया का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलान्टस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जादी पेश कर निवेदन किया कि अधीन्याया में रेस्पोंड संख्या 6/प्रार्थी ने अपीलान्ट/प्रार्थी को वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नियुक्त नहीं किया है जबकि प्रार्थी का विवादित आराजियात में 1/9 हिस्सा होकर काशतकार है । अधीन्याया के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19.11.2011 से हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अपने अधिकारों हेतु अधीन्याया के आदेश दिनांक 19.11.2011 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।
5. विद्वान वकील अपीलान्टस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधीन्याया का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट का विवादित आराजियात में 1/9 हिस्सा होकर काशतकार है किन्तु प्रार्थी/रेस्पोंड संख्या 6 अपीलान्ट को पक्षकार नियुक्त नहीं कर एकतरफा में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किये है । अपीलान्ट एवं उसकी अन्य बहिनों द्वारा अधीन्याया में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 65/2004 को प्रस्तुत कर रखी है जिसका अंतिम निर्णय दिनांक 3.11.2009 को अधीन्याया द्वारा हो चुका है जिसमें विवादित आराजी

रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा 3.81 है० भूमि बाबत् रहन, बेय, मुन्तकिल नहीं करने बाबत् पाबंद किया गया तथा रेस्पो० संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिसीवरी को खारिज किया गया तथा दिनांक 3.11.2009 का निर्णय अंतिम निर्ण है जिसकी अपील भी नहीं की गई है । बहस में आगे कथन किया कि तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद रेस्पो० संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलांटस एवं उनकी बहिनों के द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणात्मक आज्ञाप्ति, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पूर्व से सन् 2004 से लंबित है । रेस्पो० संख्या 6 ने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में काना दर्ज किया है जबकि काना रिकार्डेड खातेदार नहीं है तथा बन्ना जो कि रिकार्डेड खातेदार है उसे पक्षकार कायम नहीं किया गया है । बिना विभाजन कराये एवं घोषणात्मक वाद विचाराधीन होने के बावजूद अधी०न्याया० द्वारा कब्जे काश्त का स्थगन जारी किया गया है जो निरस्तनीय है । रेस्पो० संख्या 6 ने अधी०न्याया० के समक्ष पूर्ववर्ती वादके तथ्यों को छिपाते हुए एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी०न्याया० द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19.7.2011 निरस्त किया जावे ।

6. हमने अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० अधी० का निस्तारण करना उचित समझते हैं । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं को विवादित आराजी का 1/9 हिस्से का खातेदार होना अंकित किया है तथा अधी०न्याया० के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र में अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किये जाने से अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रथमदृष्टया प्रकट होते हैं । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.7.2011 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
7. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधी०न्याया० द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19.7.2011 के विरुद्ध यह अपील पेश की है । अधी०न्याया० की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी०न्याया० के समक्ष घासी वादी/प्रार्थी द्वारा काना, देवा, रामचंद्र पुत्रगण चौथू व मेवा व रूपा पुत्रगण भूरा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरुद्ध ग्राम रामपुरा उर्फ भूरटिया, तह० मौजमाबाद स्थित आराजी खसरा नंबर 756 रकबा 1.77 है०, खसरा नंबर 757 रकबा 0.53 है० एवं 891 रकबा 0.71 है० बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०काश्त०अधि पेश कर अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के आधे हिस्से से उसे बेदखल नहीं करे एवं राजस्व व मौके की यथास्थिति बनाये रखे । अधी०न्याया० द्वारा दिनांक 19.7.2011 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी कर अप्रार्थीगण की तलबी व जवाब के आदेश दिये गये । अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन भूमि में 1/9 हिस्से का काश्तकार है एवं अधी०न्याया० द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से उसके हित व अधिकार प्रभावित हुए हैं । हम अधिवक्ता अपीलांट के तर्क से सहमत नहीं हैं क्योंकि यदि अपीलांट अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पीड़ित है तो अधी०न्याया० के समक्ष पक्षकार बनने हेतु आवेदन कर सकता है एवं पक्षकार बनने के उपरांत चाराजोही कर सकता है । अपीलांट का यह कहीं भी कथन नहीं है कि मूल वाद में अपीलांट पक्षकार बना लिया गया हो इस कारण उसे हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का लोकस स्पटेडाई प्राप्त हो । हमें अधी०न्याया० के आदेश में कोई तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार

अपील अपीलान्ट खारिज योग्य तथा अधीन्याया द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.7.2011 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बीएलमेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बीएलमेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर